मुद्रा अवस्फीति Deflation : यह मुद्रा स्फीति की विपरीत स्थिति है

Inflation - मूल्य स्तर में वृद्धि

Deflation - मूल्य स्तर में गिरावट

जब वस्तु और सेवाओं का उत्पादन मौद्रिक आय की तुलना में अधिक तेजी से बढता है।

मंदी / अवमंदन Depression : ऐसी स्थिति तब मांग कम हो तथा वास्तविक उत्पादन नहीं बढ़ रहा हो तथा बेरोजगारी बढ रही हो, मंदी कहलाती है।

सामान्तयः GDP का दो लगातार तिमाहियों में गिरना recession कहा जाता है। जब अवमंदन के कारण एवं प्रभाव नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं तो ये पूरी अर्थव्यवस्था को चपेट में ले लेते हैं, जिसे मंदी / depression कहते हैं।

Skewflation : जब मूल्य स्तर में वृद्धि सभी या अधिकांश क्षेत्रों में न होकर एक छोटे समूह में केन्द्रित हो, स्क्युफ्लेशन कहलाता है। यह संकल्पना सर्वप्रथम आर्थिक समीक्षा 2009-10 में प्रस्तुत की गई।

फिलिप्स वक्र Phillips Curve : यह स्फीति की दर तथा बेरोजगारी के मध्य एक विलोम सम्बंध दिखाता है।

1958 (AW Phillips)

$$\text{Rate of Inflation} \propto \frac{1}{\text{बेरोजगारी की दर}}$$

ओकन नियम : इनके अनुसार बेरोजगारी में 1% की वृद्धि GDP में 2% की कमी लाती है।

उर्जित पटेल कमेटी के सुझाव पर WPI के आंकड़े Monthly जारी किए जाने लगे जबकि पहले weekly जारी होते थे। जनवरी 2015 से WPI का आधार वर्ष 2011-12 कर दिया गया है। सामान्तय राजकोषीय नीति निर्धारण में WPI को ही आधार बनाया जाता है।

CPI - खुदरा मूल्यों में होने वाले परिवर्तन की मांप करता है जो RBI की मौद्रिक नीति निर्धारण का आधार है। Feb. 2015 में CPI का आधार वर्ष 2012 कर दिया गया है जो पूर्व में 2004-05 था।

CPI के विभिन्न रूप हैं जैसे -

- औद्योगिक मूल्यों का CPI → CPI (IW) → वेतन भत्ते एवं वेतन आयोग की सिफारिश का निर्धारण का आधार
  Govt. Emp (except इलाहाम, बैंक) वेतन निर्धारण
  II श्रम सांख्यिकी आयोग की सिफारिश पर
  आधार वर्ष = 2001
- आधार वर्ष = 1986-87 कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता CPI → CPI (AL)
  इसके आधार पर कृषि मजदूरी का निर्धारण होता है
- BY 1986-87 ग्रामीण क्षेत्र से related CPI → CPI (Rural) - RL
  ग्रामीण मजदूरी (मनरेगा)
- नगरीय/शहरी क्षेत्र का CPI → CPI (U)
  उद्योगों में भिन्न क्षेत्र में कार्यरत नगरीय कर्मचारियों की मजदूरी/वेतन का निर्धारण इसी के आधार पर होता है।

CPI सम्बंधी आंकड़े नगरीय क्षेत्रों में NSSO तथा ग्रामीण क्षेत्र में डाक विभाग द्वारा एकत्र किए जाते हैं।

स्फीति की दर का निर्धारण इस आधार पर करते हैं -

$$\text{स्फीति की दर} = \frac{\text{PI चालू अवधि} - \text{PI गत अवधि}}{\text{PI चालू अवधि}} \times 100$$

(IV) नोट निर्गमन सिद्धांत को कठोर बना कर मुद्रा की आपूर्ति को रोकना।
(V) मूल्य नियंत्रण एवं राशनिंग प्रणाली के माध्यम से काला बाजारी को रोकना एवं अतिरिक्त आपूर्ति ~~की~~ की व्यवस्था करना।

इस प्रकार मौद्रिक एवं राजकोषीय उपायों के द्वारा स्फीति अवस्था में मुद्रा की चाल कम करके तथा मंदी में मुद्रा चाल बढ़ाकर साख नियंत्रण करते हैं।

<u>मुद्रास्फीति की माप</u>: यह माप मूल्य सूचकांकों के आधार पर करते हैं। मूल्य सूचकांकों के परिवर्तन से कीमत परिवर्तन की जानकारी प्राप्त होती है। किसी आधार वर्ष के Index को 100 मानते हुए चालू अवधि एवं चालू अवधि के सूचकांक निकाले जाते हैं।

$$\text{Price Index / कीमत सूचकांक} = \frac{\text{चालू मूल्य}}{\text{आधार मूल्य}} \times 100$$

सामान्तय भारत में 2 प्रकार के PI का use करते हैं।

(I) WPI (II) CPI

WPI का संकलन <u>उद्योग मंत्रालय</u> के <u>आर्थिक सलाहकार कार्यालय</u> के द्वारा करते हैं जबकि <u>CPI</u> का <u>श्रम मंत्रालय</u> का <u>श्रम ब्यूरो करता है</u> इनका प्रकाशन समान रूप से <u>CSO</u> करता है।

अभिजीत सेन समिति के सुझाव पर तैयार किए गए WPI में आधार वर्ष 2004-05 लिया गया जो अप्रै॰ 2010 से लागू हुआ। इसमें WPI निर्धारण हेतु (676) items का प्रयोग हुआ था, जिनमें 102 items - प्राथमिक क्षेत्र से, 555 items विनिर्मित क्षेत्र में एवं 19 वस्तुएं ईंधन से सम्बंधित क्षेत्र से ली गई हैं।

इनका <u>भारांक</u>

- प्राथमिक वस्तुएं - 20%
- विनिर्मित वस्तुएं - 65%
- शेष ईंधन सम्बंधी - 15%

किसान	- लाभ
पेंशन भोगी	- हानि
परिवर्तन शील आय समूह	- लाभ
स्थिर आय समूह	- हानि
सामान्य Bond / Debenture	- हानि
Inflation Bond / Debenture	- लाभ

fiscal Drag - स्फीति में वस्तु का बाजार मूल्य बढ़ता है एवं आयकरदाता की मौद्रिक आय बढ़जाती है। वह उच्च टैक्स स्लैब में धकेला जाता है यानि वास्तविक आय बढ़े बिना इस पर जो कर बोझ बढ़ता है उसे ही fiscal Drag या राजकोषीय कर्षण कहते हैं।

मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने उपाय
- राजकोषीय उपाय
- मौद्रिक उपाय

मौद्रिक उपाय में RBI द्वारा उदार एवं कठोर नीति के द्वारा credit control करते हैं। भारत में RBI - CRR, SLR, बैंक rate, repo rate, RRR आदि में वृद्धि करके मुद्रा की चाल (ऋण का प्रसार) कम किया जाता है जो कीमतें नियंत्रित करने में सहायक है। सामान्तय RBI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार मान कर ही ब्याज दरें निर्धारित करता है। OMO के अन्तर्गत RBI, security को sell करके Economy में Extra Credit को कम करता है।

RBI कठोर मौद्रिक नीति के द्वारा मुद्रा की चाल कम करती है तथा उदार नीति द्वारा money flow बढ़ाती है

भारत में सामान्तय राजकोषीय नीति का निर्धारण WPI आधारित स्फीति के अनुसार होता है।

राजकोषीय उपायों के अन्तर्गत Govt. मुद्रा की चाल नियंत्रित करने हेतु निम्न कार्य करती है

(i) संतुलित बजट बनाकर राजकोषीय घाटा कम करना जिससे वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता कम से कम हो।

(ii) बचत को प्रोत्साहित करके मुद्रा तरलता कम करना जिस के लिए राष्ट्रीय बचत योजनाएँ आरंभ होती हैं।

(iii) प्रत्यक्ष कर की दरों में वृद्धि एवं अप्रत्यक्ष कर कम करना।

मुद्रा स्फीति

मुद्रा की चाल एवं उसके मूल्य में विपरीत सम्बंध होता है अर्थात मुद्रा की चाल में वृद्धि होने से मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है।
मुद्रा की चाल में कमी - - - - - बढ़ जाता है।

मुद्रा की चाल से तात्पर्य मुद्रा का तेजी से क्रय-विक्रय में उपयोग किये जाने से होता है अर्थात् जब मुद्रा की चाल बढ़ती है तब मुद्रा तेजी से क्रय विक्रय में उपयोग की जाती है, अतः वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में वृद्धि होती है, इसी अनुपात में वस्तु एवं सेवा की पूर्ति नहीं हो पाती तो कीमतें बढ़ जाती हैं। सामान्य स्तर तक कीमत वृद्धि अनुकूल मानी जाती है जो अधिकतम वार्षिक एक अंकीय होती है, इसे नम्र स्फीति (moderade) कहते हैं। सभी देश अपनी Economy के अनुसार सामान्य स्फीति की दर का निर्धारण करते हैं। भारत के संदर्भ में यह वार्षिक दर ④ १०. [max ७१०, min २१०] निर्धारित की गई है जो Economy में निवेश को प्रोत्साहित करती है।

factors of production - भूमि, श्रम, पूंजी, साहस
↓ ↓ ↓ ↓
Factor cost = लगान + वेतन + ब्याज + लाभ = साधन लागत

दो से तीन अंक तक की मुद्रा स्फीति अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है क्योंकि इससे मांग पर विपरीत असर पड़ता है फलस्वरूप निवेश हतोत्साहित होता है, इसे दुदती (Galloping) स्फीति कहते हैं। यदि मुद्रा स्फीति की वार्षिक दर ३ अंकों से भी अधिक हो तो इसे अतिस्फीति Hyper Inflation कहते हैं। ऐसी स्थिति सांकेतिक / कागजी मुद्रा का मूल्य पूर्णतया समाप्त हो जाता है। हायपर Inflation की चर्चा सर्वप्रथम 'केगन' ने की थी।

* स्फीति एक प्रतिगामी कर है क्योंकि इसका सर्वाधिक भार वह उठाता है जिसके पास क्रय शक्ति कम है एवं जो इसके भार को उठाने में कम समर्थ है।

जान मेनार्ड 'कीन्स' के अनुसार पूर्ण रोजगार से पूर्व होने वाली कीमत वृद्धि मुद्रा स्फीति नहीं होती बल्कि यह पूर्ति में कमी के कारण के होने वाली वृद्धि होती है।

मुद्रास्फीति के कारण :

I) ऐसे कारण जिनसे मांग में वृद्धि होती है

II) - - - पूर्ति - कमी - -

III) - - - लागत में वृद्धि - -

IV) - - जो वैश्विक कारणों से उत्पन्न होते हैं

(I) { मांग में वृद्धि के कारणों से उत्पन्न मुद्रास्फीति मांग प्रेरित स्फीति कहलाती है जिसके निम्न कारण है :-

(A) जनसंख्या में तीव्र वृद्धि

(B) पूत्यस करों में कमी होना

(C) सरकारी व्यय में वृद्धि होने [subsidy] अभोक्ता की क्रय क्षमता में वृद्धि

(D) उदार मौद्रिक नीति

(E) सरकार द्वारा बड़ी मात्रा में हीनार्थ प्रबंधन करना जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है, फलस्वरूप मांग में वृद्धि होती है

(II) { पूर्ति में कमी के कारण होने वाली कीमत वृद्धि को पूर्ति प्रेरित मुद्रा स्फीति कहते है, जो विकासशील देशों में अधिक दिखती है

(A) काला बाजारी (B) आर्थिक अवरोध [हड़ताल, तालाबंदी, कच्चे माल की कमी]

(C) आर्थिक सुधारों की धीमी गति (D) अर्थव्यवस्था के वित्तीय क्षेत्र का विकसित न होना

(E) स्पष्ट कानून का अभाव
(कर -सुधार) भूमि अधिग्रहण कानून अस्पष्ट होना . श्रम कानूनों में कठोरता आदि

(F) राजनैतिक अस्थिरता

(III) { ऐसे कारण जिनमें लागत में वृद्धि होने से कीमत बढ़ती है . इसे लागत प्रेरित स्फीति कहते हैं

(A) उत्पत्ति के संसाधनों की लागत बढ़ना

(IV)
- वैश्विक कारणों से प्रभावित कीमत वृद्धि जैसे कच्चे तेल की कीमतें बढ़ना
- महत्वपूर्ण आयातित वस्तुओं की Sup. कीमतें बढ़ना
- विकासशील देशों की आय वृद्धि से वैश्विक मांग बढ़ना
- घरेलू आपूर्ति को ध्यान में रखे बिना Sup. वस्तु निर्यात करना
- आयात शुल्क में वृद्धि
- विनिमय दर की गिरावट

मुद्रास्फीति के प्रभाव

प्रभावित वर्ग		प्रभाव
उपभोक्ता	-	हानि
ऋणी	-	लाभ
ऋणदेता	-	हानि
बचत	-	कमी
व्यय	-	वृद्धि
आयात	-	वृद्धि
निर्यात	-	कमी
रोजगार	-	वृद्धि
कराशेपण	-	वृद्धि
उत्पादक, व्यापारी, निवेशक	-	लाभ

अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
(1) देश की करेंसी व मूल्य में Erosion (क्षरण)
(2) कम आय वर्ग या सीमित आय वर्ग के लोग अधिक प्रभावित होते हैं।
(3) बढ़ते मूल्य स्तर में ऋणी/उधार लेने वाले की स्थिति अच्छी होगी एवं ऋणदाता को नुकसान रहेगा क्यों वास्तविक रूप से ऋणदाता को कम भुगतान प्राप्त होता है।
(4) वास्तविक आय में कमी
(5) अल्प काल में निवेश प्रोत्साहित होता है।
(6) अल्पकाल में रोजगार बढ़ सकता है।
(7) उच्च स्फीति अंतर के कारण निर्यात में प्रतिस्पर्धात्मक कमी आती है। घरेलू वस्तु की मूल्य वृद्धि से निर्यात कम एवं आयात अधिक होने से भुगतान संतुलन गड़बड़ाता है। यह चालू खाता घाटा बढ़ाते हुए बाह्य अस्थिरता बढ़ाता है।
(8) ऊंची स्फीति दर से विदेशी विनिमय दर में कमी आती है।

मुद्रा अवस्फीति Deflation : यह मुद्रा स्फीति की विपरीत स्थिति है

Inflation - मूल्य स्तर में वृद्धि

Deflation - मूल्य स्तर में गिरावट

जब वस्तु और सेवाओं का उत्पादन मौद्रिक आय की तुलना में अधिक तेजी से बढता है।

मंदी / अवमंदन Depression : ऐसी स्थिति तब मांग कम हो तथा वास्तविक उत्पादन नहीं बढ़ रहा हो तथा बेरोजगारी बढ रही हो, मंदी कहलाती है।

सामान्तयः GDP का दो लगातार तिमाहियों में गिरना recession कहा जाता है। जब अवमंदन के कारण एवं प्रभाव नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं तो ये पूरी अर्थव्यवस्था को चपेट में ले लेते हैं, जिसे मंदी / depression कहते हैं।

Skewflation : जब मूल्य स्तर में वृद्धि सभी या अधिकांश क्षेत्रों में न होकर एक छोटे समूह में केन्द्रित हो, स्क्युफ्लेशन कहलाता है। यह संकल्पना सर्वप्रथम आर्थिक समीक्षा 2009-10 में प्रस्तुत की गई।

फिलिप्स वक्र Phillips Curve : यह स्फीति की दर तथा बेरोजगारी के मध्य एक विलोम सम्बंध दिखाता है।

1958 (AW Phillips)

$$\text{Rate of Inflation} \propto \frac{1}{\text{बेरोजगारी की दर}}$$

ओकन नियम : इनके अनुसार बेरोजगारी में 1% की वृद्धि GDP में 2% की कमी लाती है।

निर्यात विकास केन्द्र

तिरूपुर - होजरी, बुनाई उद्योग
पानीपत - हथकरघा
अलेप्पी - नारियल रेशे एवं निर्मित सामान
मेरठ - खेल सामान
खुर्जा - मिट्टी के बर्तन
वापी (अंकलेश्वर) - रसायन
भागलपुर - बुनाई
मुरादाबाद - ब्रास वेयर हैंडीक्राफ्ट
लुधियाना - मशीनरी, होजरी
सूरत - रत्न आभूषण
जालंधर - खेल सामान
रानीपत - चमड़ा
नागपुर - हस्त शिल्प
विशाखापत्तनम - मछली
अलीगढ़ - पीतल ताले
आगरा - चमड़ा footware
कांचीपुरम् - रेशम
सेलम - हस्त शिल्प
शिवाकासी - माचिस
अम्बाला - वैज्ञानिक उपकरण
जामनगर - ब्रास पार्ट्स
राजकोट - इंजन पम्प
बड़ौदा - मशीन उपकरण

White level ATm : Tata Communication and payment Sol^n. के बाद Prism payment services Pvt. ltd एवं muthoot finance ने भी ATm स्थापित किए। Bank के अलावा अन्य कम्पनी द्वारा स्थापित ATm को white level ATm कहते हैं।

TC PGL → [इंडि कैश] → ठाणे → महाराष्ट्र - जून -2013
Prism → भैद्रे गाँव → रायगढ़ → महाराष्ट्र → [मनीस्पाट] → Jan 14
muthoot → नई दिल्ली → feb -14

Dutch Disease – पहले से आयातित किसी संसाधन के विकसित होने के कारण उसके आयात में कमी आने आती है। परिणामतय: करेन्सी के विदेशी मूल्य का Depreciation होता है। इससे देश के उद्योगों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति में कमी को ही Dutch Disease कहते हैं।

Dumping: घरेलू बाजार के मूल्य से कम पर वस्तु का निर्यात ही Dumping है। इसका Aim विदेशी बाजार को Capture करना है।

over Heating: ऐसी क्रिया जिससे अधिक मांग सृजित हो एवं उत्पादन क्षमता बढ़ने से उत्पादन स्तर भी ऊँचा हो जाए एवं आयात बढ़ जाए। यह आंतरिक रूप से स्फीतिक दबाव पैदा करती है एवं बाह्य रूप से प्रतिकूल व्यापार संतुलन की स्थिति को जन्म देता है।

* जिस देश में जमा रखा हो वह उस देश की करेंसी के अलावा दूसरे देश की करेंसी मे है तो इसे Offshore deposits (अपतटीय जमा) कहते है।

कैयर्न्स समूह – कृषि वस्तुओं के निर्यात हेतु बाजार विस्तारित करने वाले (19) देशों का समूह

Deemed export: ऐसे निर्यात व्यवहार जिनमें पूर्ति की जाने वाली वस्तु देश के बाहर नहीं जाती। इनका भुगतान ₹ या विदेशी मुद्रा में होता है।

Ex. अग्रिम लाइसेंस के अन्तर्गत वस्तु की पूर्ति, EPG निर्यात

में किया जाने लगा। आगे चलकर (1993-94) के बजट में ₹ को चालू खाते के अन्तर्गत पूर्ण परिवर्तनीय बनाने से सम्बंधित प्रस्ताव रखा। फलस्वरूप 19 Aug 1994 में CA के पूर्णतया परिवर्तनीय ₹ लागू की गई। RBI के पूर्व Dy. Gov. S. S. तारापोर की अध्यक्षता में पूँजी खाते में परिवर्तनीय प्रणाली लागू करने से सम्बंधित मुद्दे पर विचार हेतु कमेटी का गठन हुआ। जिन्होंने इसके पक्ष में सुझाव दिया है जिस पर पुनर्विचार हेतु सलीम गंगाध्यरन की अध्यक्षता में एक कार्यदल गठित हुआ है।

* FERA 1973 — विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम
FOREIN EXCHANGE REGULATORY ACT

* FEMA 1999 — विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम
foreign exchange management Act

Int. मुद्रा की आवाजाही को नियंत्रित करने हेतु (1973) में FERA लागू हुआ जिसका उद्देश्य भारत में विदेशी मुद्राओं का संरक्षण करना था But उदारीकरण के बाद बड़ी मात्रा में मुद्रा की आवाजाही को देखते ही इसके सरलीकरण की आवश्यकता हुई अतः 1 जून 2000 से FERA के स्थान पर अधिक उदार FEMA लागू किया गया। किन्तु 2 वर्ष का समय पूर्व में लम्बित मामलों के निपटान हेतु दिया गया, अतः 1 June 2002 से अंतिम रूप से FEMA लागू हुआ।

* FERA एवं FEMA की तुलना :

(I) FERA का उद्देश्य भारत में विदेशी मुद्रा का संरक्षण करना था जबकि FEMA का उद्देश्य विदेशी व्यापार को बढ़ाना देने हेतु विदेशी मुद्रा की आवा-जाही को सरल बनाना है, अतः FEMA अधिक उदार है।

(II) FERA के अन्तर्गत अवैध रूप से मुद्रा की आवाजाही से सम्बंधित case का निपटारा Criminal Case के तहत होता था जिसमें अर्थ दंड के साथ ½ जेल का भी प्रावधान था किंतु FEMA में ऐसे case को Civil case

Important Points

* के. एम. शर्मा कृष्णन कमेटी - सड़क सुरक्षा
* NABARD में सरकार की हिस्सेदारी - 99.60 %.
* SBI द्वारा 'पहली उड़ान' और 'पहला कदम' खातों की शुरुआत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों हेतु की गई।
* Rhyme, Rythm & Truth in Economics के लेखक - J.K. Mehta
* Happy Planet Index का आधार - जीवन संतुष्टि, जीवन प्रत्याशा, पारिस्थितिक स्थिति
* आयोजन संबंधी सर्वोदय Plan - जयप्रकाश नारायण द्वारा 1950 में लाया गया
* विकसित देशों की बेरोजगारी - चक्रीय एवं घर्षण जनित
* बहु आयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा का विकास संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा हुआ।
* देश के I औद्योगिक नीति प्रस्ताव - 1948 की घोषणा श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने की
* बेसेल मानक का निर्धारण BIS (Bank of International Settlement) द्वारा किया जाता है।
* पात्रगत विदेशी निवेश (QPI) - FPI के अंतर्गत विदेशी नागरिकों द्वारा खरीदे गए share.
* सूखा प्रभावित Block में मनरेगा के तहत रोजगार दिवस की संख्या को बढ़ाकर 150 किया।
* के० एम० चंद्रशेखर समिति - विदेशी Portfolio निवेश.
  सुंदर समिति - मोटर वाहन Act.
  विवेक देवराय समिति - भारतीय रेलवे की पुनर्संरचना
  विमल जालान समिति - नए Bank license.

विदेश व्यापार नीति

केन्द्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री द्वारा 1 April 2015 को भारत की नई व्यापार नीति जारी की गई जो वर्ष 2020 तक भारत के विदेश व्यापार के दिशा निर्धारण करेगी। इसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं :

(I) वैश्विक निर्यातों में भारत की भागीदारी को बढ़ाकर 3.5% करना.

(II) अगले 5 वर्षों में देश के निर्यात को 900 Billion $ तक लाना.

(III) इस नीति में वस्तु निर्यात, तथा सेवा निर्यात योजना आरंभ की गई हैं। उत्पाद योजना के तहत निर्धारित बाजारों में भारत के वस्तु निर्यातकों को 2-5 % तक प्रोत्साहन राशि दी जायेगी जबकि दूसरी योजना के अन्तर्गत सेवा निर्यातकों को 5% प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।

(IV) यह व्यवस्था विशेष SEZ पर भी लागू होंगी।

(V) इस नीति में वरीयता के आधार पर विश्व के विभिन्न बाजारों को 3 वर्गों में बाँटा गया :

I) max priority प्राप्त बाजार, इन्हें परम्परागत बाजार की श्रेणी में रखा है, जिसमें US, कनाडा, EU मिलाकर 20 देश हैं.

II) उभरते हुए बाजार - इसमें USSR, अफ्रीका तथा द० अमेरिकी से 139 देश शामिल हैं।

III) अन्य बाजार - इसमें 70 देश शामिल हैं।

(VI) निर्यातों में वृद्धि हेतु केन्द्र four. राज्यों के साथ मिलकर एक निर्यात प्रोत्साहन मिशन, व्यापार विकास प्रोत्साहन परिषद का गठन होगा।

(VII) इस नीति को Make in India, Digital India, Skill India से जोड़ा गया

(VIII) विदेश व्यापार की समीक्षा बैठक वार्षिक न होकर 2½ वर्ष में होगी।

Special Economic Zone : [SEZ] - स्थापना - चीन की तर्ज पर

किसी देश के भीतर स्थापित ऐसे आर्थिक क्षेत्र जहाँ उत्पादित max Product को Export किया जाये, उन्हें SEZ कहेंगे। Govt. ऐसे क्षेत्रों को विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता दे निर्यात के लिए प्रोत्साहित करती हैं। 1st. में सर्वप्रथम (1965) में कांडला (गुजरात) में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र [EPZ] की स्थापना हुई थी।

SEZ Act - 2005 के द्वारा सभी EPZ को SEZ में परिवर्तित किया। यह Act. 2 feb 2006 से लागू हुआ। वर्तमान में SEZ के सर्वाधिक स्वीकृत मामले महाराष्ट्र में जबकि सर्वाधिक गतिशील SEZ Tamilnadu में हैं। → ⑦EPZ जो SEZ बने - कांडला, सूरत, सांताक्रुज, चेन्नई, विशाखापट्टनम, फाल्टा (WB), नोयडा.

Exclusive Economic Zone
अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) :- किसी देश की समुद्री सीमा के अन्तर्गत स्थापित वह क्षेत्र जिसके आर्थिक प्रयोग का एकाधिकार उस देश के पास होता है ऐसे क्षेत्र के EEZ कहते हैं.

भारत का EEZ : 200 Nautical mile.

EEZ में हाइड्रो से सम्बंधित वैज्ञानिक एवं तकनीकी दस्तावेज UNO के सामने पेश होते हैं।

निर्यात सम्वर्धन पूंजीगत सामान योजना
Export promotion Capital Goods scheme : (EPCGS)

यह निर्यातों को बढ़ावा देने वाली Imp. योजना है, जिसमें Exporter को रियायती आयात शुल्क पर पूंजीगत सामान के आयात की अनुमति दी जाती है। वर्तमान प्रावधान के अ/c EPCGS का लाभ उठाने हेतु 75% min. निर्यात की शर्त का पालन आवश्यक है।

* देश का Ist export promotion Industrial Park - सीतापुर, March 1991
* UP का Ist EPIP - कासना (नोयडा)

Tidel Park : Hardware - software Industry की आधारिक संरचना की सभी सुविधाएँ एक ही जगह provide करने हेतु तारामणि (चेन्नई) में 4 July 2000 को अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना हुई, जिसे "टाइडल पार्क" कहा गया।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से सम्बंधित सामान्य परिवर्त्तन नियम

GAAR : General Anti Avoidance Rule :-

यह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवहार से सम्बंधित ऐसे नियम हैं जिनके द्वारा कोई देश Int. money flow सम्बंधी नीतियों में Transparency लाता है। सर्वप्रथम डा० प्रणव मुखर्जी ने GAAR लागू करने से सम्बन्धित व्यापार रखा किंतु विदेशी निवेशकों की प्रतिक्रिया को देखते हुए पार्थ सारथी शोम समिति ने इसे April 2016 तक स्थगित करने का सुझाव दिया। साथ-ही इन्होंने मारीशस के वास्तविक निवेशकों को GAAR के दायरे से बाहर रखने तथा NRI's को GAAR में सम्मिलित करने का सुझाव भी दिया।
शोम समिति ने GAAR लागू करने हेतु Negative list एवं लाभ की मौद्रिक सीमा 3 Cr करने की सिफारिश की

* **TOBIN TAX :** टोबिन (US) ने 1971 में विदेशी विनिमय दरों के तीव्र परिवर्तनों को नियंत्रित करने हेतु Tax लागू करने का सुझाव दिया। इसे TOBin Tax कहा गया।

इसी Tax का संशोधित रूप ही Robinhood Tax है जिसमें सभी प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवहार पर Tobin Tax लगाने का प्रावधान है।

* **Benefits of SEZ :**
* यह एक Duty free क्षेत्र है, जिसे व्यापारिक क्रिया Duty, Tarrif की दृष्टि से विदेशी क्षेत्र के रूप में लेते हैं।
* SEZ units वस्तु, सेवा निर्यात करेंगी, [Including कृषि वस्तुएँ]
* आयात हेतु License जरूरी नहीं।
* यूनिट द्वारा खरीदी गई वस्तुओं पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नहीं लगेगा,
* Custom officer, export-import का routine check up नहीं करेंगे।

* **Demerits of SEZ :**
* राजस्व में कमी
* भू अधिग्रहण प्रक्रिया
* local market से स्थान हटकर export पर लगेगा,
* Powerful एवं क्षेत्रीय एकाधिकार बढ़ेगा

* Economic growth Inc.
* Employment बढ़ेगा
* export बढ़ेगा
* foreign Investors आकर्षित होंगे
* वैश्विक तकनीक एवं skills आकर्षित होंगी
* भारतीय एवं विदेशी firm की प्रतियोगिता बढ़ेगी।

निर्यात के भाग → Merchandise export - MEIS
→ service export - SEIS

MEIS : Merchandise export from India scheme [उपहार दर = 2-5%]

SEIS : SErvice Export from India scheme [उपहार दर = 3-5%]

MEIS का उद्देश्य : ऐसी तकनीकें एवं वस्तुएँ जो भारत में उत्पादित हैं, जिनके निर्यात में रोजगार क्षमता एवं भारतीय प्रतिस्पर्धा/प्रभावित हो. में कमी लाना।
वर्तमान में चल रही निम्नलिखित ⑤ स्कीमों को मिलाकर MEIS चालू की गई है।
Focus Product scheme, Focus Market scheme, Market Linked focus scheme, Agriculture Infrastructure Incentives scheme एवं विशेष कृषि ग्रामीण उद्योग योजना।

SEIS का उद्देश्य : भारत में सूचित सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहन देना यह योजना service from India scheme के स्थान पर शुरू हुई।

TRIMS : Trade Related Investment Measures.

यह एक प्रकार का प्रतिबंध है जो देश अपने विनियोगों पर लगाते हैं। अक्सर इनका प्रयोग विकासशील करते हैं। कोई देश ऐसे Trims लागू नहीं करेगा जो WTO के नियम विरूद्ध हों।

TRIPS : Trade Related Intellectual Property Rights.

Indo - अँशीशम DTAC = 1983

* शैल कम्पनी : सामान्य व्यापारिक लगने जैसी वे कम्पनी जो सिर्फ एक खाली खोल की तरह होती हैं। यह सिर्फ पैसे का प्रबंधन करने हेतु बनी जाती हैं। आमतौर पर ये छोटे द्वीपीय देश, जहाँ बैंकिंग गोपनीयता अच्छी हो एवं कर बहुत कम हो, वहाँ खोली जाती हैं। Ex. मकाऊ, बहामास, पनामा etc.

* **Arbitrage** : विदेशी मुद्राओं का एक साथ इस Aim से क्रय विक्रय करना ताकि बाजार में प्रचलित विदेशी विनिमय दरों के अंतर का लाभ उठाया जा सके ।

* **Hedging** : अपने को विभिन्न जोखिमों से होने वाली हानि से सुरक्षित करना (Covering of export Risks)

* **Nostro Accounts** - Our A/c with you. विदेश में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खाते ही नोस्ट्रो A/c हैं। खाता जिस देश में होगा, मुद्रा भी उसी की होगी ।

* **Vostro A/c** : Your A/c with us.

BID – जिस दर पर डीलर विदेशी मुद्रा क्रय करेगा
ASK – " " " " " " विक्रय "
SPREAD = ASK rate - BID rate

* **Vehicle Currency** : किसी देश की मुद्रा जब Int. Trade में use हो जिसमे वो पार्टी न हो । Ex: Dollar.

* NEER - Nominal Effective Exchange rates [नॉमिनल प्रभावी विनिमय दर]
REER - Real - - - [वास्तविक " " "]
विदेशी विनिमय बाजार में प्रचलित किसी विदेशी मुद्रा की 1 unit का परेलू मूल्य, NEER है. Ex 1 $ = 65 ₹
जब इसमें स्फीति या मूल्य स्तर का समायोजन करे तो यह REER कहलाता है।
RBI, भारत तथा विदेशी व्यापारिक भागीदार देश के सम्बंध में CPI use करता है।

* **Freeport** : port / Airport जहाँ शुल्कीय टैरिफ न लगे

* **Interpot** : ऐसा बन्दरगाह जहाँ वस्तुओं का आयात हो एवं without any Processing के पुनर्निर्यात कर दी जाएँ ।

* **Ad-valorem Tariff** – जब टैरिफ आयातित वस्तु के मूल्य के एक fixed अनुपात या % में व्यक्त हो ।

* **Countervailing Duty** :- जब कोई देश अपने निर्यात को subsidized करे ताकि दूसरे देश में उसकी प्रतिस्पर्धा सस्ती हो एवं वहाँ का बाजार प्राप्त हो सके, इसकी प्रतिक्रिया में दूसरा देश आयात पर जो Duty लगाए, वह निर्यात subsidy के प्रभाव को निरस्त कर दे तो उसे Countervailing Duty कहते हैं। यह Duty सीमा शुल्क में नहीं अपितु वस्तु के उत्पाद शुल्क में निरोधित होगी।

विदेश व्यापार

विदेश व्यापार के अन्तर्गत एक वित्त वर्ष में होने वाले समस्त आयात - निर्यात, वैश्विक आर्थिक नीतियाँ, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों आदि का अध्ययन किया जाता है। इस संदर्भ में भारत के विदेश व्यापार सम्बंधी विवरण को चार भागों में बाँटा गया है।

① विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ एवं संगठन.
जैसे - Imf, WB, Wto .....

② ऐसे आर्थिक संगठन जिनमें भारत की भूमिका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्षता महत्वपूर्ण है.
जैसे → G-20, BRICS (2009), SAARC → SAFTA, ...

③ विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय आर्थिक समझौते [RTA]....

④ भारत के विदेश व्यापार की संरचना एवं दिशा.

हाइट Plan - USA
कीन्स Plan - ब्रिटेन

① विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ एवं संगठन

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण पर विचार करने हेतु 1944 में अमेरिका के ब्रेटनवुड्स शहर में एक सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें 44 देशों ने भागीदारी की जिनमें भारत भी सम्मिलित था। इस सम्मेलन में तत्कालीन परिस्थितियों से सम्बंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं को स्पष्ट किया जो इस प्रकार हैं :

WTO

L2 - P6

ministerial conferance
- All countries
- Director General
- 2 years में Meeth
- 9th - Baali

General Council
- Day to Day काम
- जेनेवा में बैठते हैं
- Bodies
  - Trade review
  - Dispute settlement

DG
- 4 साल reappoint
- सचिवालय - जेनेवा

मिलकर

function * Tariff, non Tariff Barrier बढ़ाना
* LDC की भी मदद [व्यापार में]
  - Public Procurement
  - Absurd Quality Control
    - SPS
    - TBT
  - Subsidy

GS-2 Policy Affecting
GS-3 Food processing
} Exam → PON

2014: अल्फांसो आम (India) एवं Egg Plant (US) ने EU ने प्रतिबंध लगाया।

SPS: Sanitary & Photosanitary measures
कोई देश बाहर से आयतित माल पर प्रतिबंध लगा सकता है अगर उसे लगे कि ये माल उसके Plants, animals, या human lives के लिए नुकसानदेय है। इस हेतु Food Agricultural Org. का Codex standard use होगा।

Measures taken: भारत ने कहा कि अब सिर्फ Agriculture processed food Production Export development Authority (APEDA) द्वारा Authorise माल ही export हो, अतः 2015 में Ban हटाया।

(i) वैश्विक व्यापार के सम्बंध में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा की तरलता
(ii) प्रतिस्पर्धात्मक रूप से मुद्रा के अवमूल्यन [मुद्रा मुल्य] एवं विनिमय दर को नियंत्रित करना
(iii) पिछड़े एवं विकासशील देशों की आधारभूत संरचना में निवेश करने के लिए दीर्घकालीन पूँजी की आवश्यकता
(iv) वैश्विक स्तर पर परस्पर विश्वास को बढ़ावा देकर उदारीकरण के द्वारा वैश्विक अर्थव्यवस्था के विचार को लागू करना।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) - (1) MD - कैमिल गट्ट (बेल्जियम)

उपरम दो समस्याओं के समाधान हेतु 27-Dec 1945 को IMF का गठन किया गया किन्तु इसने अपना कार्य May 1946 में आरंभ किया। IMF के संस्थापक सदस्यों की संख्या (30) थी, जिसमें भारत भी सम्मिलित था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। वर्तमान IMF सदस्य संख्या 189 है। अंतिम सदस्य - नौरू (द० प्रशांत द्वीपीय राष्ट्र)

IMF द्वारा प्रतिवर्ष World Economic outlook नाम से प्रकाशन जारी की जाती है। इस संस्था की प्रमुख समस्या भुगतान संतुलन शेष है जिसका समाधान करने हेतु अल्पकालीन ऋण देता है। साथ ही साथ यह प्रतिस्पर्धात्मक अवमूल्यन को नियंत्रित करता है। IMF की सदस्यता प्राप्त करने वाले देशों के लिए यह आवश्यक है कि विश्व बैंक की सदस्यता प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त सदस्य को एक निश्चित मात्रा में अनिवार्य पूँजी का अंशदान करना होता है, जिसका निर्धारण उस देश के कोटे के आधार पर किया जाता है। सदस्य देश के कोटे का निर्धारण 3 बातों को ध्यान में रखकर होता है

* सम्बंधित देश की विश्व व्यापार में भागीदारी
* उस देश की प्रतिव्यक्ति राष्ट्रीय आय
* " " " अर्थव्यवस्था का आकार / आर्थिक विकास दर (GDP).

IMF में किसी देश के कोटे के आधार पर ही उस देश के वित्तीय अंशदान, मताधिकार, वित्तीय सहायता etc. का निर्धारण होता है
* यह कोटा उस देश के विदेशी मुद्रा भंडार का महत्वपूर्ण भाग होता है।

वर्तमान में सर्वाधिक कोटे वाले देश :

USA (16.8%)
जापान (16.25%)
जर्मनी (15.83%)
फ्रांस (4.3%)
UK (4.3%)
भारत (2.8%) → Eight position

SDR मूल्य - 13114 [13114] million SDR.

Special DRAWING RIGHT - विशेष आहरण अधिकार

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा की तरलता की समस्या के समाधान हेतु जन० 1970 में IMF द्वारा एक कृत्रिम मुद्रा जारी की गई, जिसे विशेष आहरण अधिकार [SDR] कहा जाता है जो सदस्य देशों के मध्य परस्पर भुगतान हेतु उपयोग की जाती है। SDR लेन देन की कोई भौतिक इकाई नहीं है बल्कि एक बुकिंग काई है जो IMF द्वारा सृजित विदेशी मुद्राओं की फंड माप्त पर निर्गत किया जाता है। सदस्य देशों में इसकी स्वीकार्यता के कारण ही SDR को Paper Gold कहते हैं।
upto 1970 1SDR = 1$ = 0.88 gm Gold
प्रारंभ में 1 SDR का मूल्य 1 $ के समान था किन्तु वर्तमान में SDR के मूल्य निर्धारण हेतु 4 IMF मुद्राओं के आधार पर होता है :

- US Doller [44%]
- EURO [34%]
- Pound [11%]
- YEN [11%]

* Depositors ने IMF में जो SDR जमा किया, उस पर ब्याज मिलेगा, जबकि जिन्होंने SDR उधारी में लिया वो ब्याज देंगे।
* SDR Deposit पर 0.05% Interest IMF Pay करता है।
* SDR Contribution ⇒ voting Power.

Imf के समान WB भी UNO का एक अभिकरण है। प्रतिवर्ष वर्ल्ड Development Report नाम से WB वैश्विक Economy की समीक्षा करता है। WB सदस्य देशों को आसान शर्तों पर दीर्घ कालीन ऋण देता है, इसकी स्थापना Imf के साथ ही ब्रेटनवुड्स सम्मेलन के पश्चात की गई। सदस्य देशों द्वारा WB में वित्तीय अंशदान किया जाता है किन्तु ये अंशदान बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋण की सीमाएँ निर्धारित नहीं करता बल्कि इसमें सदस्य देशों के उत्तरदायित्व एवं प्रशासकीय अधिकारों का स्पष्टीकरण होता है।

* WB ⑤ संस्थाओं का एक समूह है जिनका वर्गीकरण कार्य विभाजन के आधार पर किया गया है

① IBRD [Int. Bank for Reconstruction & Development]
अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक

(I) IDA [Int. Development Association]
अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ

(II) IFC [International Finance Corp.]
अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम

(IV) MIGA [Multilateral Investment Guarantee Agency]
बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी

(V) ICSID [Int. centre for settlement of Investment dispute]
[निवेश सम्बंधी विवादों का निपटारा करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र]

अर्थपुस्त संस्थाओं में IBRD की स्थापना Imf के साथ ही Dec 1945 में की तथा इसने कार्य July 1946 में शुरू किया। वास्तव में IBRD को भी WB के रूप में जाना जाता है। यह संस्था

सदस्य देशों में आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देकर विकासशील देशों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है।

अल्पविकसित गरीब एवं अल्पविकसित देशों को अल्पब्याज दर ऋण (No Interest) प्रदान करने हेतु 1960 में IBRD की सहायक संस्था के रूप में IDA की स्थापना हुई, इसे WB की उदार ऋण खिड़की कहते हैं। जो सदस्य देशों को 3 तथ्यों के आधार पर ऋण सुविधा देता है

I - Poverty
II - Project
III - Priority

} 3-P

भारत को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु 1958 में India club Consortium की स्थापना हुई. जिसका नाम 1994 में बदल भारत विकास मंच कर दिया।

IFC - 1956. ये विकासशील देशों को ऋणपत्रों के माध्यम से निवेश की सुविधा उपलब्ध कराता है अतः ये संस्था विकासशील देशों के उद्योगों हेतु ऋणपत्रों के माध्यम से विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराता है।

MIGA की स्थापना 1988 में हुई, ये संस्था सदस्य देशों को परस्पर निवेश संबंधी जोखिम की गारंटी प्रदान करता है। यह निवेश संबंधी विवादों का निपटारा करने हेतु 1966 में ICSID का गठन हुआ।

* भारत ICSID की दौड़कर सभी का सदस्य है

WB के प्रथम महानिदेशक - पीटर सदरलैंड

WORLD TRADE ORGANISATION

ब्रैटनवुड्स सम्मेलन में WTO की स्थापना का विचार रखा गया था, किंतु यह तत्कालीन समय स्थापित नहीं हो सका अतः 1947 के हवाना सम्मेलन में भारत सहित (23) देशों ने परस्पर व्यापारिक प्रतिबंधों में कमी लाने से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसे GATT [General Agreement on Tariffs & Trade] व्यापार एवं शुल्क संबंधी सामान्य समझौता कहा गया।

तत्पश्चात् GATT के उरुग्वे समझौते के अन्तर्गत 1 जन. 1995 से WTO अस्तित्व में आया जिसने GATT का स्थान लिया।

* most favoured Nation का सिद्धांत GATT से related है।

WTO एक स्वतंत्र, स्थायी एवं वैधानिक संस्था है जो उदारीकरण को बढ़ावा देने के aim से Int. व्यापार संबंधी नियम बनाता है।

WTO के संस्थापक सदस्य - 76 थे [Including India]

वर्तमान सदस्य संख्या → 164 [अंतिम - Afganistan]

मुख्यालय - जेनेवा

इसका मंत्रिस्तरीय सम्मेलन प्रति (2) वर्ष में होता है।

Dec. 2015, नैरोबी (केन्या) में सम्मेलन का आयोजन हुआ।

WTO संरक्षणवादी नीति के विरुद्ध नियम बनाता है। इसी के तहत WTO ने subsidy को दो भागों में बांटा।

I) प्रतिबंधात्मक subsidy, इसके अन्तर्गत Amber Box तथा Red Box subsidy आते हैं।

II) अनुमोदन कारी subsidy, इसमें Green Box, Blue Box subsidy आते हैं।

* WTO के दोहा (2001) सम्मेलन में चीन, ताइवान को इसका सदस्य बनाया।

ऐसे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 1000 $ से कम होती है उन्हें प्रतिबंधित subsidy के संदर्भ में छूट प्राप्त है। जबकि अन्य देशों में यह पूर्णतया प्रतिबंधित है।

अनुमोदनकारी subsidy का प्रयोग अन्य देशों के व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखकर किया जाता है।

Govt. व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव को आधार मानते हुए WTO ने Subsidy का विभाजन (4) वर्गों में किया

(I) **GREEN Box Subsidy** : Govt. द्वारा घरेलू स्तर पर प्रदान की जाने वाली ऐसी आर्थिक सहायता जो पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण etc. के रूप में दी जाती है। R&D Training

Ex. कृषि क्षेत्र से सम्बंधित विभिन्न अनुसंधान कार्यक्रम
कौशल विकास से सम्बंधित skill India prog.

इस Subsidy की सीमा का निर्धारण नहीं होता, इस पर किसी प्रकार का विवाद नहीं
no limit By WTO

(II) **Blue Box Subsidy** : इसमें किसी क्षेत्र में होने वाली हानि की भरपाई (not dir. with production) हेतु Govt. प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता देती है। WTO ने इसकी max limit का निर्धारण किया जो वस्तु की मूल्य के max. 10% है। ये subsidy Iceland, स्लोवानिया जैसे देशों में है

(Ex). भारत के संदर्भ में किसान को दी जाने वाली MSP.

(III) **अम्बर Box Subsidy** → इस प्रकार की subsidy में Govt. द्वारा अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान करके घरेलू उद्योगों एवं कृषि को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बने रहने हेतु MSP दी जाती है जो प्रतिबंधित Subsidy में आता है।

Ex. निम्न ब्याज दर के कृषि ऋण. MSP regime.
मुफ्त बिजली, Subsidy युक्त Urea etc.

India opposed Amber Box

Developed - 5%
Developing - 10%

(9) Red Box subsidy : जब Govt. द्वारा आयातों को प्रतिबंधित एवं निर्यातों को प्रोत्साहित कर, वैश्विक व्यापार में घरेलू अर्थव्यवस्था उद्योगों को बढ़ावा देते हैं तो इसे Red Box subsidy कहते हैं। यह सर्वाधिक विवादित subsidy है।

1986 में GATT के उरूग्वे सम्मेलन में बौद्धिक सम्पदा सम्बंधी अधिकारों को लेकर विवाद हुआ जिसका स्पष्टीकरण करने हेतु तत्कालीन GATT के महानिदेशक आर्थर डंकन के नेतृत्व में एक प्रस्ताव पारित किया। 1994 के मारेकश सम्मेलन में इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए जिसमें बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के 7 भागों में वर्गीकृत किया

1. Copyright
2. Trade mark
3. भौगोलिक संकेतक
4. औद्योगिक रूपरेखा
5. Patent
6. एकीकृत परिपथीय रूपरेखा
7. व्यापार सम्बंधी गुप्त सूचनाएँ

(10) ऐसे आर्थिक संगठन जिनमें भारत की भूमिका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण है :

① BRICS : Also called R-5 इन्हें मुद्रा - रीमल, रूबल, रूपया, रैनमिंबी रेंड
ब्रिम अवधारणा के प्रतिपादक - जिम ओ नील

वर्ष 2008 की US मंदी के पश्चात् रूस, भारत, चीन ने वर्ष 2009 में एक संगठन की स्थापना की जिसे RIC नाम से जाना गया। 2009 (रूस) प्रथम सम्मेलन में ही ब्राजील को सम्मिलित करने के बाद इसे BRIC नाम दिया। (III) सम्मेलन (चीन) 2011 में SA अफ्रीका को शामिल करने पर इसे BRICS नाम से जाना गया।

BRICS की स्थापना का मुख्य Aim US मुद्रा पर निर्भरता को कम करना

तथा वैश्विक व्यापार में पश्चिमी देशों का प्रभुत्व कम करना था, जो तत्कालीन US मंदी से ग्रस्त थे। 2009 के प्रथम सम्मेलन में US $ के स्थान पर SDR को मानक मुद्रा स्वीकार करने के संदर्भ में विचार हुआ किन्तु चीन के विरोध के कारण इस पर सहमति नहीं बनी। BRICS के नईदिल्ली (2012) सम्मेलन में सर्वप्रथम भारत ने BRICS BANK की स्थापना का विचार रखा। तथा 2014 ब्राजील सम्मेलन में BRICS BANK स्थापना समझौते पर हस्ताक्षर हुए।

BRICS BANK - कुल अधिकृत पूंजी = 100 अरब $ [पांचों देशों ने समान भागीदारी से 20 अरब fund बनाया है]

मुख्यालय - शंघाई (चीन)

I अध्यक्ष - के० वी० कामथ (भारत)

BRICS BANK को अस्थ देश WB के विकल्प के रूप प्रयोग करेंगे। IMF के विकल्प के रूप में एक आकस्मिक fund का गठन किया गया है. जिसकी कुल पूंजी 100 अरब $ है।

max. Contribution - चीन (41 अरब $)

min " - द० अफ्रीका (5 अरब $)

भारत, रूस, ब्राजील - 18 अरब $

* ICICI बैंक भारत में ब्रिक्स बैंक का 1st साझेदार बना।

चीनी Govt. के प्रस्ताव पर 47 देशों ने जून 2015 में एशियाई अवसंरचनात्मक निवेश बैंक [AIIB] सम्बंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए।

मुख्यालय - बीजिंग

यह एक अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो एशियाई क्षेत्र के बुनियादी विकास के लिए वित्तीय सहायता देगा। इसे एशियाई विकास बैंक के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।

SAARC - दक्षेस

South Asian Association for Regional Co-operation.

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ.

आर्क की स्थापना का विचार सर्वप्रथम (1980) में बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर्रहमान ने दिया। इसी के आधार पर 8 Dec. 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 7 देशों के शासनाध्यक्षों ने मिलकर आर्क की स्थापना की। नई दिल्ली सम्मेलन 2007 में अफगानिस्तान को 8वें सदस्य के रूप में शामिल किया।

आर्क सदस्य	भारत श्रीलंका बांग्लादेश नेपाल	भूटान मालदीव पाकिस्तान अफगानिस्तान

सामान्यतः प्रत्येक 2 वर्ष पर SAARC सम्मेलन का आयोजन होता है।

SAARC सम्मेलन (2014) - 18 वां → काठमांडू (नेपाल)

प्रस्तावित (2016) → 19 वां → इस्लामाबाद (पाकिस्तान)

हाल ही में सम्पन्न 18 वें सम्मेलन में आर्क के अन्तर्गत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, जैसे- Custom Union, Common Market, मौद्रिक संघ, South Asian Economic Union [SAEU] जैसे समझौतों पर सहमति बनी है। साथ ही साथ SAARC food bank Agreement एवं SAARC पशुधन ऋण बैंक की स्थापना का विचार भी इस सम्मेलन में रखा गया।

आर्क से सम्बंधित संस्था. केन्द्र

* मुख्यालय - काठमांडू
* आर्क विवि. - नई दिल्ली
* आर्क कृषि केन्द्र - ढाका
* आर्क मौसम विज्ञान एवं अनुसंधान केन्द्र - ढाका
* आर्क Disaster management Centre - भारत

* म्यान्मार एवं आस्ट्रेलिया को आर्क के पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा थिम्पू के 16वें आर्क सम्मेलन में दिया गया [2010]

* सार्क मानव संसाधन विकास केन्द्र - इस्लामाबाद
* सार्क ऊर्जा केन्द्र - इस्लामाबाद
* सार्क सूचना केन्द्र - नेपाल
* सार्क ने 2010-20 के दशक को सार्क अन्तर्क्षेत्रीय सम्पर्कता दशक.
* सार्क forestry centre - भूटान

G-20

यह विश्व के 20 औद्योगिक एवं विकासशील देशों का संगठन है। इसमें 19-1 देशों के साथ European Union (20) को 1 देश के रूप में शामिल किया गया है। 1999 में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक जुट करने हेतु बर्लिन में 20 देशों के Fm तथा Central Bank के गवर्नरों का एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसे G-20 नाम दिया। इस समूह का मुख्य उद्देश्य वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने हेतु औद्योगिक एवं विकासशील देशों को एक मंच पर लाना है। कुल वैश्विक व्यापार में G-20 देशों की भागीदारी (80%), GDP में (85%) तथा वैश्विक जनसंख्या में (67%) की भागीदारी है। सामान्यतः G-20 का सम्मेलन प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। वर्ष 2015 का सम्मेलन तुर्की के अंतालया शहर में हुआ
2016 (प्रस्तावित) - (चीन)

* G-20 के Paris (2011) सम्मेलन में भारत के सुझाव पर Gold. मौद्रिक प्रणाली सुधार के लिए G-20 कार्यदल का गठन हुआ, जो पूंजी प्रवाह तथा उसका प्रबंधन, वैश्विक नकदीकरण का मापन एवं SDR की भूमिका पर विचार करेगा।

* G-15 → 1989 - 17 सदस्य → विकासशील देश
मुख्यालय - जेनेवा.
* ASEAN plus three → चीन, जापान, द० कोरिया (1999)
* ASEAN क्षेत्रीय मंच की स्थापना - 1994 (1996 में भारत सदस्य बना)

ASEAN - Association of South-East Asian Nations

दक्षिण पूर्वी देशों का संघ
एशियाई

* यह Free Trade Block का एक Ex. है

8 Aug (1967) को बैंकाक घोषणा के तहत (5) दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों ने आसियान का गठन किया।

वर्तमान सदस्य संख्या - (10)

{ मुख्यालय - जकार्ता }

संस्थापक सदस्य	
	इंडोनेशिया
	फिलीपींस
	मलेशिया
	सिंगापुर
	थाइलैंड

ब्रूनेई
वियतनाम
लाओस
म्यान्मार
कम्बोडिया (1999)

* आसियान दिवस - 8 Aug
* आसियान रीजनल forum - 1994
  10 आसियान शब्द + 11 वार्ताकार देश
* आसियान चार्टर - 20 Nov 2007 } sign
  ↓ सिंगापुर
  2008 से लागू

मुख्य Aim → दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। भौगोलिक स्थिति के कारण भारत Asean का सदस्य नहीं है किन्तु 23 जुलाई (1996) को भारत को आसियान में पूर्ण वार्ताकार का दर्जा मिला. अतः भारत, ASEAN की सभी बैठकों में भागीदारी करता है तथा इसे अपनी बात कहने का अधिकार है किन्तु मतदान का नहीं।

Nov. 2015 में ASEAN सम्मेलन कुआलालम्पुर (मलेशिया) में आयोजित हुआ
* सम्मेलन - 2 वर्ष में

ADB - ASIAN DEVELOPMENT BANK
एशियाई विकास

एशियाई (प्रशांत क्षेत्रीय) देशों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने हेतु (1966) में ADB का गठन हुआ।

* मुख्यालय - मनीला (फिलीपींस)
* वर्तमान सदस्य संख्या - (67)
* भारत संस्थापक सदस्य है।

ADB की स्थापना "ESCAP" के तत्वाधान में हुई।

ADB सदस्य देशों को रियायती दर पर दीर्घकालीन ऋण देता है।
सामान्यतः अध्यक्ष पद पर जापानी की नियुक्ति होती है, तथा (3) उपाध्यक्षों में

एक USA, एक यूरोप एवं एक एशियाई देशों से चुना जाता है।
ADB का विकल्प AIIB.

+ G-7/8

- गठन में तत्कालीन फ्रांस राष्ट्रपति वैलारी गिस्गार्ड ने Imp. भूमिका निभाई

विश्व के 6 पूंजीवादी एवं विकसित देशों ने (1975) में G-6 का गठन किया। USSR के विघटन के पश्चात् संघ के विभिन्न देशों में पूंजीवादी विचारधारा का उदय हुआ, अतः वैश्विक व्यापार में रूस को रणनीतिक साझेदार के रूप में सम्मिलित किया गया तथा इसे G-8 नाम से जाना गया। किन्तु यूक्रेन विवाद के कारण 2014 में 2014 में रूस को संगठन से बाहर किया गया।

रूस (1997) में शामिल हुआ। सम्मेलन - प्रत्येक वर्ष जून-जुलाई

USA, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान
1976 में शामिल

+ शंघाई सहयोग संगठन

शंघाई-6 / G-6

SCO - SHANGHAI Co-operation ORganisation

सीमावर्ती विवादों के निपटारे के लिए (1996) में (5) देशों ने मिलकर इस संगठन की स्थापना की [रूस, चीन, कजाखिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान]. छठे सदस्य के रूप में उजबेकिस्तान को सम्मिलित करने पर इसे शंघाई-6 नाम दिया।

वर्ष - 2005 में अस्ताना सम्मेलन भारत, पाक, ईरान को इस संगठन में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया।

वर्ष 2008 के रूस में सम्पन्न सम्मेलन में India, Pak. को समूह में स्थाई सदस्यता दी गई।

SCO की वर्तमान सदस्य संख्या - (8)

अगला प्रस्तावित सम्मेलन = अस्ताना (कजाकिस्तान)

* SCO सदस्य बनने के बाद मध्य एशिया की गैस एवं तेल उत्खनन परियोजनाओं तक भारत की पहुँच हो जायेगी।

* आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन

34th member - स्लोवेनिया
Asian Member - इजरायल

OECD: Organisation for Economic

एक संगठन के तौर पर भारत का max. विदेश व्यापार OECD देशों के साथ होता है जिनकी सदस्य संख्या (34) है। II WW के बाद 1948 में यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्स्थापित करने हेतु पेरिस में सम्मेलन का आयोजन हुआ तथा यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन (OEEC) अस्तित्व में आया। Sep. 1961 में इसी का नाम बदलकर OECD किया गया।

मुख्यालय - (पेरिस) (फ्रांस)

यह संगठन परस्पर आर्थिक कल्याण हेतु नीतियों का समर्थन तथा विकासशील देशों के कल्याण में sup. भूमिका निभाता है।

* अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION

Int. स्तर पर श्रम सामाजिक न्याय हेतु (1919) में ILO की स्थापना हुई तथा 1946 में इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया।

मुख्यालय - जेनेवा

यह संगठन Int. श्रम मानकों का निर्धारण करता है।

* खाद्य एवं कृषि संगठन

FOOD & AGRICULTURE ORGANISATION.

(1945) में UNO की Agency के रूप में FAO की स्थापना हुई।

मुख्यालय - (रोम)

यह संगठन विभिन्न देशों में पोषण तथा रहन-सहन के स्तर में सुधार लाने का प्रयास करता है। साथ ही साथ ↓ कृषि सम्बन्धी सम्बंधी समस्याओं वैश्विक स्तरपर

European Parliament का प्रथम चुनाव = 1979.

के समाधान हेतु इन्हीं शासायनों में सम्बंधित मानकों का निर्धारण करता है।

EU
max. सीट - जर्मनी (99)
min - माल्टा (5)

यूरोपीय संघ

EUROPEAN UNION

EU में विस्तार का निर्णय Nice Treaty - 2000 में लिया गया। नाइस - फ्रांस का शहर

यूरोपीय देशों के एकीकरण के उद्देश्य से 1958 में रोम में एक संधि हुई जहाँ यूरोपीय आर्थिक समुदाय [EEC] का गठन हुआ। USSR के विघटन के पश्चात EEC की सदस्य संख्या में विस्तार हुआ अतः वैश्विक चुनौतियों का सामना करने हेतु इसकी संरचना में परिवर्तन करना आवश्यक हुआ। 1993 में EEC का नाम बदलकर European Community कर दिया गया। लिस्बन संधि 2007 में इसका नाम EU किया गया। लिस्बन संधि 2009 से लागू हुई। वर्तमान में EU की सदस्य संख्या 28 है। ब्रिटेन के बाहर जाने से सदस्य संख्या 27 है। लिस्बन संधि के द्वारा EU के क्षेत्राधिकार में 6 बिंदुओं को शामिल किया गया।

- सदस्य देश परस्पर Custom यूनियन का संचालन करते हुए वस्तु, सेवा निवेश एवं अन्य आर्थिक संसाधनों का स्वतंत्र आदान प्रदान करेंगे।
- सदस्य देश आंतरिक बाजारों में प्रतिस्पर्धा सम्बंधी नियमों का निर्धारण परस्पर सहमति से ही करेंगे।
- मौद्रिक नीति निर्धारण में सदस्य राष्ट्र परस्पर सहयोग करेंगे।
- समुद्री संसाधनों के उपयोग सम्बंधी नियमों का स्पष्टीकरण होगा।
- सामान्य व्यापार सम्बंधी अन्य नीतियाँ

वर्तमान में EU के कार्यों का निष्पादन इनकी 7 आधारभूत संस्थाओं द्वारा किया जाता है

- यूरोपीय संसद
- Council of EU
- European Commission
- European Council
- European Central Bank.
- European Court of Auditors.
- European Court.

* यूरो ज़ोन

28th Member - क्रोएशिया

सर्वप्रथम 1993 की मॉस्ट्रिच संधि में सर्वप्रथम यूरोपीय देशों के मौद्रिक एकीकरण के संदर्भ में एक साझा मुद्रा यूरो पर सहमति बनी। फलस्वरूप 1 जनवरी 1999 में यूरो चलन में आया। आरंभ में EU के 11 देशों ने यूरो को अपनाया था। वर्तमान में EU के 19 देशों ने यूरो को परस्पर लेन देन में प्रयोग किया [last country - लिथुआनिया (19वां)]

(19) देशों के इस समूह को ही यूरोजोन कहते हैं।

यूरोजोन में सम्मिलित होने एवं बने रहने हेतु निम्न शर्तों का पालन जरूरी है।

- मुद्रा स्फीति की नियंत्रित दर जो EU में सर्वोत्तम निष्पादन करने वाले 3 देशों के औसत स्फीति की दर से Max. 1.5 % हो गा।
- निम्न ब्याज दर
- सर्वोत्तम निष्पादन करने वाले प्रथम 3 देशों के Av. ब्याजदर से Max 2 %.
- सरकारी ऋण की Max. सीमा किसी भी समय GDP के 60 % से अधिक नहीं होना चाहिए।
- वार्षिक बजटीय घाटा Max. GDP का 3% से ज्यादा न हो।

→ नार्वे, स्विटजरलैंड EU के Member नहीं हैं।

---

* EXTRA *

* NAFTA : North America free trade Agreement (1994)
II worlds largest FTA.

* APEC : Asia - Pasant Economic Cooperation (1989)
↑ FTA
मुख्यालय - सिंगापुर
सदस्य - 21
{ विश्व मामलों में एशिया प्रशांत की आवाज }
भारत APEC सदस्य नहीं है।

* OPEC : Organisation of petroleum exporting Countries. (1960)
1960 ↑ बगदाद
मुख्यालय - वियना
सदस्य - (14) { 5 संस्थापक, 9 अन्य देश } → वर्तमान सदस्य = (15)

- ✓ ईरान
- ✓ कुवैत
- ✓ सउदी अरब
- ✓ वेनेजुएला
- ✓ इराक
- अल्जीरिया
- अंगोला
- इक्वेडोर
- इंडोनेशिया
- लीबिया
- नाइजीरिया
- कतर
- UAE

विश्व का 45% तेल भंडार OPEC राष्ट्रों के पास है।
इंडोनेशिया - 2009] सदस्यता त्यागी
इराक - 2019]

* **BIMSTEC** : Bay of Bengal Initiative for Multi Sector Technical and Economic cooperation.

स्थापना - 1997 - बैंकॉक

Members - 7.

बंगाल की खाड़ी में लगे 4 देशों बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाइलैंड का व्यापारिक समूह (BISTEC) में म्यान्मार, भूटान, नेपाल भी शामिल हुए।

* **Benelux** ← Belgium, Netherland, Luxemberg — स्थापना - 1948, मुख्यालय - ब्रूसेल्स } व्यापारिक सहयोग

* **EFTA** : European free Trade Association

स्थापना - 1960 (स्टॉकहोम) → 7 देश → outer seven → ब्रिटेन, स्विटजरलैंड, आस्ट्रिया, स्वीडन, डेनमार्क, पुर्तगाल, नार्वे

Aim सदस्य राष्ट्रों में आपसी व्यापार हेतु Custom Duty & कर कटौती.

मुख्यालय - जेनेवा.

* **मर्कोसुर** {MERCOSUR} :

↑ spanish word → दक्षिण शंकु का साझा बाजार

1 Jan 1995 को ब्राजील, अर्जेन्टीना, पराग्वे, उरुग्वे ने दक्षिण साझा बाजार स्थापित किया।

6th सदस्य - वेनेजुएला

* **UNCTAD** : United Nations Conference on Trade & Development.

अंकटाड - संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास संगठन/सम्मेलन

मुख्यालय - जेनेवा

14 वां सम्मेलन - जुलाई 2016 → नैरोबी (केन्या) प्रस्तावित

* 4 वर्ष के अंतराल में इसका अधिवेशन होता है।
* IMF की इसकी सभाओं में स्थाई प्रतिनिधित्व प्राप्त है।
* अंकटाड के सुझाव रचनात्मक होते हैं, जिनके पालन हेतु किसी राष्ट्र को बाध्य नहीं कर सकते।

* **NAFTA** : 1992 — मुख्यालय → ओटावा

सदस्य - 3 → USA, कनाडा, मैक्सिको.

* IBSA : 2003 ⑬ { South Africa, India, Brazil } गठन - ब्राजीलिया

* GCC - Gulf cooperation Council - 25 May 1981
मुख्यालय - रियाद सदस्य देश = 04
अरब देशों के मध्य आर्थिक सहयोग हेतु

विश्व का 50% से अधिक व्यापार RTA के माध्यम से होता है जो WTO के कार्य क्षेत्र के बाहर है।

-विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय व्यापारिक समझौते (RTA) -

Int. स्तर पर जब दो या अधिक देश परस्पर व्यापार को बढ़ावा देने हेतु कोई समझौता करते है तो उसे 'क्षेत्रीय व्यापारिक समझौता' कहते हैं, जिसके विभिन्न स्वरूप होते है।

① वरीयता के आधार पर व्यापार का समझौता
Preferential Trade Agreement (PTA) : जब दो या अधिक देश द्विपक्षीय व्यापार में अन्य देशों की अपेक्षा परस्पर वरीयता के आधार पर व्यापार करते है।

Ex. भारत एवं सार्क देशों के मध्य SAPTA. वर्तमान में भारत एवं EU के मध्य वरीयता के आधार पर ही व्यापार होता है।

② मुक्त व्यापार समझौता
Free Trade Agreement (FTA) : इसके अन्तर्गत समूह के देश परस्पर करमुक्त वस्तुओं के आयात-निर्यात का समझौता करते हैं। इसमें सेवाओं को सम्मिलित नहीं किया जाता। FTA के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि यह सदस्य देशों के मध्य ही किया जाए, जबकि समूह से बाहर के देशों हेतु एक अलग नीति का पालन होता है। इस स्थिति में सदस्य देशों के मध्य व्यापार करमुक्त प्रणाली रहती है।

Example: सार्क देशों के मध्य FTA [SAFTA]
यूरोपीय देशों के मध्य FTA [EFTA]

• लैटिन अमेरिकी देशों के मध्य FTA [LAFTA]

③ Custom Union : इस समझौते में किसी समूह के सदस्य देश समूह के बाहर अन्य देशों के साथ भी करमुक्त वस्तुओं के आयात निर्यात का समझौता करते हैं अर्थात CU के तहत FTA का विस्तार समूह के सदस्य देशों के साथ-साथ समूह के बाहर के देशों के साथ भी होता है।

Ex. आसियान समूह के साथ भारत का करमुक्त व्यापार समझौता.

④ व्यापक आर्थिक सहयोग एवं व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CECA & CEPA

CECA - Comprehensive Economic Cooperation Agreement.

CEPA - Comprehensive Economic Partnership Agreement.

CECA समझौते में वस्तुओं के साथ-साथ सेवाओं के भी कर मुक्त आयात निर्यात का समझौता किया जाता है जबकि CEPA में वस्तुओं, सेवाओं एवं निवेश के भी स्वतंत्र आदान प्रदान सम्बंधी समझौता होता है।

Ex - Indo-[ASEAN, EU, GCC]. (CEPA - Indo-Japan)

⑤ साझा बाजार Comman Market : जब दो या अधिक देश वस्तुओं, सेवाओं, निवेश के साथ-साथ उत्पादन के सभी संसाधनों का परस्पर स्वतंत्र रूप से आदान प्रदान करते हैं तो इसे साझा बाजार समझौता कहते हैं। यह तब स्थापित होता है जब दो या अधिक देश Custom Union बनाते हैं।

Ex : European Economic Community (EEC), Benelux

⑥ आर्थिक संघ Economic Union : यह RTA का सर्वाधिक व्यापक स्वरूप है। इसमें दो अधिक देश वस्तुओं, सेवाओं, निवेश, उत्पादन के संसाधनों का स्वतंत्र आदान-प्रदान करने के साथ-साथ राजकोषीय एवं मौद्रिक नीति तथा औद्योगिक नीतियों को भी परस्पर साझा करते हैं।

Ex European Union.

* CEPA : जब एक बार Tariff की औसत दर कम हो जाए तो मौद्रिक विनिमय दर में कमी का व्यापारिक ढाँचे एवं घरेलू उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति पर प्रभाव पड़ेगा।

FTA के भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव :

① FTA के तहत साझेदार देश को अधिक लाभ होने की संभावना है जबकि भारत का निवल लाभ या तो Negative होगा या बहुत कम। भारत का प्रमुख लक्ष्य Net export को Maximize करना होना चाहिए।

② FTA करते समय घरेलू क्षेत्र विशेष की समस्याओं-मुद्दों को ध्यान नहीं रखा जाता

③ FTA के परिणामतय नए प्रकार का प्रतिलोमी ड्यूटी ढांचा उभरा है, जिसमें FTA साझेदारों द्वारा निर्मित वस्तुओं पर Duty, कच्चे तेल (माल) की Duty की अपेक्षा कम होगी, इससे स्थानीय विनिर्माण हतोत्साहित होगा।

FTA के निष्कर्ष : * FTA के द्वारा max profit तब होगा जब यह विकसित एवं विकासशील देश के मध्य हो।

* कठिन, कष्टप्रद संघनात्मक समायोजन जरूरी है ताकि राजनीतिकरण से बचा जा सके।

* FTA का लाभ सदस्य देशों तक सीमित हैं, यह हितकारी नहीं।

* एडम स्मिथ (wealth of Nations - 1776) ने बताया कि दो देश निरपेक्ष लागत अंतर के आधार पर कार्य करें तो ऐसे व्यापार में दोनों को लाभ होगा एवं कुल उत्पादन बढ़ेगा।
* Principals of Political Economy & Taxation (1817) - डेविड रिकार्डो
* अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक स्वरूप का श्रेय - हेक्शर ओहलिन

Spot Exchange : जब विदेशी विनिमय की delivery on the spot हो
forward Exchange : जब एक पार्टी निश्चित विदेशी विनिमय की मात्रा एक भावी तिथि पर घरेलू मुद्रा के बदले एक निश्चित Rate से स्वीकार करे।
Swap operations : एक साथ किसी मुद्रा के लिए forward क्रय से उसी मुद्रा का spot विक्रय करना या forward विक्रय हेतु उसी मुद्रा को spot क्रय करना, swap कहलाता है, इसे हम Double Deal / दोहरा व्यवहार भी कहते हैं।

भारत एवं अन्य देशों के मुख्य सम्पन्न RTA

① भारत - जापान CEPA समझौता - Feb-2011
समझौता के द्वारा 10 वर्षों में भारत अपना सीमा शुल्क में 90%. जापान 97% कमी करेगा।

② भारत - द० कोरिया CEPA - Aug. 2009

③ भारत - ASEAN Custom union समझौता / CEPA - July 2015
Indo - Asean देशों के मध्य Aug. 2009 में Custom Union समझौता हुआ जो 1 Jan 2010 से लागू हुआ समझौते के द्वारा दोनों पक्षों के मध्य वर्ष 2016 तक लगभग 4000 वस्तुओं के करमुक्त आयात निर्यात पर सहमति बनी Sep. 2014 में इसे Extend करते हुए CEPA का रूप दिया गया जो 1 July 2015 से लागू हुआ।

④ भारत - मलेशिया CEPA
ASEAN के 10 सदस्यों में एक मलेशिया के साथ CEPA Feb 2011 में सम्पन्न हुआ जो July 2011 से लागू है जबकि अन्य ASEAN देशों से CEPA July - 15 में लागू हुआ

* सार्क देशों के मध्य PTA / FTA [SAPTA / SAFTA]

सर्वप्रथम सार्क के (6th) शिखर सम्मेलन (1991) कोलम्बो में वरीयता के आधार पर व्यापार करने सम्बंधी विचार रखा गया जिसे SAPTA कहा गया 11 April 1993 में SAARC के (7th) सम्मेलन ढाका में SAPTA पर हस्ताक्षर हुए। Dec. 1991 से SAPTA लागू हुआ।
Jan 2004 में इस व्यापार का विस्तार करते हुए SAPTA को SAFTA में परिवर्तित किया जो 1 Jan 2006 से लागू हुआ। इसके तहत सार्क के कम विकसित देश अपने सीमा शुल्क में (20%) कमी करेंगे। जबकि अत्यधिक कम विकसित देश अपने सीमाशुल्क में (30%) कमी करेंगे। अन्य देशों के लिए (15%) शुल्क मुक्त का प्रावधान रखा गया है।

सार्क के दो देश Indo-Pak ने SAFTA हस्ताक्षर तो किए but अभी तक पाक ने भारत को सर्वाधिक वरीयता प्राप्त देश का दर्जा नहीं दिया जबकि भारत ने पाक को यह दर्जा 1996 में ही दे दिया। अतः वर्तमान में दोनों देशों के मध्य सूची में दर्ज वस्तुओं तक ही व्यापार सीमित है, जिसको Positive list कहते हैं।

भारत के विदेश व्यापार की संरचना एवं दिशा :

कुल वैश्विक व्यापार में भारत की भागीदारी लगभग 2% है जो निर्यात में 1.6% तथा आयात में 2.7% है।

* भारत का max. विदेश व्यापार : चीन, USA, UAE, सउदी अरब
* क्षेत्रानुसार भारत का max. विदेश व्यापार : एशिया, यूरोप, उ० अमेरिका, अफ्रीका
* भारत के निर्यात की प्रमुख मदें (Items) →

① Petroleum उत्पाद ② रत्न आभूषण ③ वस्त्र ④ रसायन

* भारत के आयात की प्रमुख मदें →

① Crude oil ② रत्न एवं आभूषण ③ रसायन ④ इलेक्ट्रानिक Items

मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता का सिद्धान्त :

पूर्ण परिवर्तनीयता में तात्पर्य भुगतान संतुलन के समस्त लेन देन में स्वतंत्र विनिमय प्रणाली (परिवर्तनीय) से होता है। अर्थात् ऐसी स्थिति में Int. मुद्रा का स्वतन्त्र रूप से विनिमय होता है। भारत में उदारीकरण से पूर्व स्थिर प्रणाली के आधार पर विनिमय दर का निर्धारण होता था। इसी संदर्भ में 3 बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन (1949, 1966, 1991) किया गया किंतु उदारीकरण के पश्चात् विनिमय प्रणाली को उदार करने की आवश्यकता हुई, इसी संदर्भ में 1992 में भारत में दोहरी विनिमय प्रणाली आरंभ हुई इसके अंतरगत विनिमय दर के 40% भाग का निर्धारण स्थिर दर से तथा 60% भाग का निर्धारण परिवर्तनीय दर

3 July 1991-last

L 3-PS

IMF

- Board of Directors
  - All nations
  - Fin. min / Governor
  - Annual meet
- Executive Board
  - 24 Director
  - Reserved 5 (seat)
- Managing Director
  - 5 years (Reappoint)
  - Washington
  - Int. staff.

function: Surveillance Global, BOP crisis, Technical assistance (Advise)

Reforms in IMF:

① उभरते देशों का Quota बढ़ाना।
② उभरते देशों का Quota बढ़ाने में गरीब देशों का कम किया, जो असहमति का कारण है।
③ सभी directors elected होंगे, ⑤ seat जो reserve है वे भी reserve नहीं रहेंगी।
④ 5 साल में review होगा।
⑥ Proposal हेतु 85% vote share चाहिए यानि US vote 17% है फिर कुछ भी Proposal Accept हेतु US का साथ जरूरी।

Criticism of IMF:

* surveillance में fail रहे, (Mexico - 1995, East एशिया 1997) Subprime crisis.
* SDR rate High
* Quota reforms नहीं ला पाए।